अर्द्धशा० पत्र सं-1771/सत्तर-3-2021

डॉ० दिनेश शर्मा

उप मुख्यमंत्री एंव
नेता, सदन, विधान परिषद्, उ०प्र०

99-100, विधान भवन,
लखनऊ

दिनांक: 02/08/2021

OFFICE OF THE VICE-CHANCELLOR
03 AUG 2021
No. 345
LUCKNOW UNIVERSITY

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 6276
तिथि 04/08/2021
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ—226007

प्रिय कुलपतिगण,

29 जुलाई, 2020 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा की गयी। उक्त घोषणा के पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक शासनादेश जारी किये गये हैं। तत्क्रम में आप सभी द्वारा नीति पर विभिन्न स्तरों पर विमर्श आयोजित कर नीति के कियान्वयन हेतु प्रयास किये गये। परन्तु कोविड 19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत उक्त कार्य में व्यवधान आ गया। पुनः कुछ शैक्षिक संस्थानों ने नीति के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही की है। इसको अधिक गति देने की अवश्यकता है।

2– अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड–19 जनित विषम परिस्थितियो के दृष्टिगत एव राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- उक्त के दृष्टिगत 05 सितम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि आपके शिक्षकों द्वारा 75000 से अधिक ई–कंटेन्ट तैयार करके डिजिटल लाइब्रेरी पर उपलब्ध कराया गया, जिसका लाभ अद्यतन 5.50 लाख छात्र–छात्राओं द्वारा लिया जा चुका है। अनुरोध है कि छात्र हित में उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध शिक्षण सामग्री का भरपूर उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा पद्वति को बढावा दिये जाने हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों में स्थित 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में छात्र–छात्राओं हेतु 160 प्री–लोडेड टैबलेट्स उपलब्ध कराये गये हैं, जिनमें शिक्षण सामग्री पहले से ही उपलब्ध करायी गयी है प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्थित 120 अन्य राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में छात्र–छात्राओं हेतु 1080 प्री–लोडेड टैबलेट्स उपलब्ध कराये जाने के लिए इस वर्ष धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- साथ ही, प्रदेश के छात्रों के मध्य डिजिटल डिवाइड को कम करने एव राज्य के तहसील एव ब्लाक स्तर पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ई–लर्निंग पार्क, वाई–फाई, इण्टरनेट कनेक्शन एव एक्सेस विकसित करने हेतु प्रति महाविद्यालय 05 कम्प्यूटर, 05 प्रिन्टर, 03 टेबल कुर्सी एवं वाई–फाई एवं इण्टरनेट के लिए धनराशि भी इस वर्ष उपलब्ध करायी गयी है।

कृपया आप व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रदेश की डिजिटल लाइब्रेरी के साथ–साथ प्री–लोडेड टैबलेट्स तथा ई–लर्निंग पार्क का भी भरपूर उपयोग सुनिश्चित करवाए।

AR-1473 05/8/2021

GA-1424 05/8/21

A.R.(G.A)

Reqy 04/8/2021

Registrar

07/08/21

प्रभारी (G.A) 05/08/2021 (AR)

Dy-CM

P.T.O

GA-11992

संख्या–............................ दिनांक–..........7/8/2021..........

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / इंचार्ज, ल0वि0वि0।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
3. डीन, आर.ए.सी. / डीन, रिसर्च / डीन, एकेडमिक, ल0वि0वि0।
4. समस्त प्राचार्य / प्राचार्य, संयुक्त, ल0वि0वि0।
5. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
6. परीक्षा नियत्रंक, ल0वि0वि0।
7. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
8. मुख्य अभिरक्षिका, ल0वि0वि0।
9. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
10. प्रोफेसर / इंचार्ज, अभियात्रिकी संकाय, ल0वि0वि0।
11. ओ0एस0डी0, आईएमएस, ल0वि0वि0।
12. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समस्त को ई–मेल के माध्यम से पत्र प्रेषित करने तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइड पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

Neeraj 5.8.2021 Narain 5.8.21 05/8/21

3– प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्य में बढ़ावा दिये जाने हेतु रिसर्च एण्ड डेबलेपमेन्ट योजना वर्ष 2020 से लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के 84 प्रस्ताव व विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित 56 प्रस्तावों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।

अनुरोध है कि अपने स्तर पर समीक्षा करके अवमुक्त की गयी धनराशि का ससमय सदुपयोग सुनिश्चित करें तथा इस वर्ष हेतु उत्तम श्रेणी के प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित करें।

- साथ ही, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का भी कम से कम 70 प्रतिशत उपयोग करके शासन को उपयोग प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

4– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के उद्देश्य से न्यूनतम समान पाठ्यकम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र द्वारा समय–समय पर विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में अधिकांशतः कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

5– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के समग्रता से कियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा में प्रयास करने हेतु अनुरोध है:–

नीति के कियान्वयन पर किये गये कार्यों की वर्ष भर की समीक्षा एवं आगामी वर्ष की योजना का रोडमैप तैयार कर के इस पर सम्बद्ध संस्थानों के प्राचार्यों के साथ बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

समीक्षा हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है:–

- सभी आचार्यों (फैक्ल्टी) ने शिक्षा नीति का समग्रता से अध्ययन कर लिया है।
- महाविद्यालयों में कितनी संगोष्ठिया, वेबीनार आदि आयोजित किए गए हैं।
- कियान्वयन हेतु दृष्टि–पत्र (ब्लूप्रिंट) तैयार किया गया है।
- विश्वविद्यालयों / संस्थान के विभिन्न विभागों के द्वारा कियान्वयन की योजना बना ली गयी है।
- कितने महाविद्यालयों मे कियान्वयन समिति / टास्क फोर्स का गठन किया गया है?
- छात्रों की सहभागिता हेतु क्या विशेष प्रयास हुए है?

उपरोक्त विषयों के संदर्भ में निम्नानुसार आगामी योजना का भी विचार करना उपयुक्त होगा:–

- छात्रों आलेख, शोध–पत्र के प्रस्तुतीकरण आदि प्रतियोगिता आयोजित करना।
- आचार्यों (प्रोफेसर्स) हेतु सेमिनार तथा सभी के लिए तीन दिन से सात दिन के रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना।
- सभी महाविद्यालयों में कियान्वयन समिति / टास्क फोर्स द्वारा 31 अगस्त तक कम से कम एक संगोष्ठी / वेबीनार का आयोजन करवाना।
- विषयों एवं विभागों के अनुसार कमबद्ध एक वर्ष की योजना बनाना आदि।

6– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी कियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में

अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें।

7– महोदय, हो सकता है कि आपके विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उपरोक्त सभी या इससे भी अधिक बिन्दुओं पर कार्य हुआ होगा। मै मात्र पुनः स्मरण हेतु आपको सुझाव प्रेषित कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समग्रता से कियान्वयन होने से **"देश की शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा" अर्थात भारत विश्वगुरू बनने की दिशा में अग्रसर होगा।**

(डॉ० दिनेश शर्मा)

1– प्रो० अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति, ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	2– डॉ० अखिलेश कुमार सिंह, कुलपति, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3– प्रो० अशोक मित्तल, कुलपति, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।	4– प्रो० आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
5– प्रो० आलोक कुमार राय , कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।	6– प्रो० आनन्द के० त्यागी, कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
7– प्रो० कल्पलता पाण्डेय, कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।	8– प्रो० कृष्ण पाल सिंह, कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
9– प्रो० जे०वी० वैशम्पायन, कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।	10– प्रो० निर्मला एस० मौर्या, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
11– प्रो० नरेन्द्र कुमार तनेजा, कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	12– प्रो० रवि शंकर सिंह, कुलपति, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

13– प्रो0 राजेश सिंह, कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	14– प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
15– प्रो0 सुरेन्द्र दुबे, कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।	